यूपी में चुनाव : गुंडाराज, महागुंडाराज या राक्षसराज

- मनोज कुमार झा

मोदी सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई है, इसमें कोई शक नहीं रह गया है। इस सरकार की नीतियों की वजह से दुनिया में भारत की छवि पर भी बुरा असर पड़ा है। पाकिस्तान हो या चीन, मोदी सरकार की विदेश नीति असफल साबित हुई है। बहरहाल, सरकार को इससे ज्यादा मतलब नहीं है। अमेरिका की दलाली करने पर भी वहां उसे कुछ खास हासिल नहीं हुआ। हालत ये है कि हर जगह इस सरकार का मजाक उड़ रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी जैसा दलाल सरकार के मंत्रियों और अफसरशाहों पर सवाल उठाता है और कोई कुछ नहीं कर पाता। दो साल के दौरान ही मोदी सरकार की दिवालिया नीतियों की वजह से इसे अब तक की सबसे खराब सरकार बताया जा रहा है। हालत ये है कि जो मंत्री सरकार की दो साल की उपलब्धियों का बखान करने जनता के बीच जा रहे हैं, उन्हें ईंट-पत्थरों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।

विगत दिनों हुए राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को कोई खास सफलता नहीं मिल पाई। इसके पीछे इस सरकार के प्रति जनता का असंतोष है जो दिन-ब- दिन बढ़ता ही चला जाएगा। सिर्फ असम में भाजपा को सफलता मिली। इसके पीछे कांग्रेस का वहां लंबा शासन और उसके प्रति लोगों का असंतोष ही एकमात्र वजह है। अब भाजपा की निगाह उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों पर है, जो अगले साल होना है। यूपी विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यूपी का फ़ैसला साबित कर देगा कि भाजपा का भविष्य क्या होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरह से यूपी चुनावों के लिए प्रचार भी शुरू कर दिया। वैसे भी इनका काम महज चुनाव-प्रचार करना ही रहा है। विधानसभा चुनावों के लिए शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने इतना प्रचार किया हो, जितना मोदी ने किया है। यूपी में मोदी ने अपनी जनसभा में बहुत ही भद्दे तरीके से प्रचार शुरू किया। उन्होंने कहा कि एक मौका देकर देखो, काम नहीं कर सका तो लात मार कर भगा देना। ये लात मार कर भगा देने वाले इनके जुमले की बहुत निंदा हुई। दरअसल, प्रधानमंत्री से इस तरह की सड़क छाप भाषा की उम्मीद कोई नहीं करता। यह वाकई बहुत ही दुख और आश्चर्य की बात है कि एक प्रधानमंत्री ऐसी घटिया भाषा का इस्तेमाल करे। पर मोदी ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा रखी ही कब ? बिहार चुनाव हो या पश्चिम बंगाल का चुनाव, हर जगह उन्होंने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भी घटिया भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं। बिहार इलेक्शन के दौरान 'पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे' वाला उनका जुमला काफी चर्चित हुआ था। जीत न बिहार में मिली, न बंगाल में। अब देखना है कि यूपी में क्या होता है। इसमें कोई शक नहीं कि यूपी में जीत के लिए भाजपा अपना सब कुछ दांव पर लगा देगी। यूपी की जीत से ही उसे राज्यसभा में बहुमत हासिल हो सकता है और आगे सरकार को ताकत मिल सकती है। यूपी और बिहार वो राज्य हैं जो केंद्र की राजनीति को तय करते रहे हैं। लेकिन वहां मोदी ने शुरुआत ही बुरी की है। ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं कि मोदी के अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके खिलाफ बहुत ज्यादा असंतोष है। काशी को क्योटो बना देने वाला जुमला बेकार साबित हुआ। भाजपा चुनावों में अपनी साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति को छोड़ नहीं सकती। यही उसकी एकमात्र पूंजी है। यही कारण है कि यूपी चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होते ही भाजपा नेतृत्व ने कैराना का राग छेड़ दिया। कैराना से हिंदुओं के पलायन को बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, लेकिन यह टांय-टांय फिस्स हो गया। बीजेपी नेताओं की सोच थी कि इस मुद्दे को उभार कर वे साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण की शुरुआत कर देंगे और लोगों के बीच वैमनस्य पैदा कर, कुछ दंगे-फसाद करवा कर चुनाव में उसकी फसल काट लेंगे। पर कैराना का सच सामने आ गया। लेकिन भाजपा के मंसूबे अभी भी वही हैं। इसकी वजह ये है कि इसके पास दूसरा कोई मुद्दा है ही नहीं। विकास की भद्द तो बढ़ती महंगाई से ही पिट गई। मोदी सरकार ने बेशर्म फैसला करते हुए रक्षा समेत सभी क्षेत्रों को भी एफडीआई के लिए खोल दिया। जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई, वह काम भाजपा ने कर दिखाया, जबकि विपक्ष में रहने के दौरान इसने एफडीआई का जबरदस्त विरोध किया था। इसके अलावा, दो वर्षों में सरकार ने एक भी ऐसा कदम नहीं उठाया है, जिससे जनता को तनिक भी राहत मिली हो। इस वजह से चंद भाजापाइयों और संघ समर्थक जूठनखोरों के अलावा सबके मन में मोदी सरकार के प्रति भारी असंतोष है।

अब सवाल ये है कि भाजपा यूपी में जीत के लिए क्या करेगी ? ये देखने वाली बात होगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि वह राममंदिर का मुद्दा उठाएगी। यद्यपि इस मुद्दे में अब कोई दम नहीं रहा, पर ऐसी घोषणाएं की जा रही हैं कि 2019 तक मोदी के प्रधानमंत्री रहते अयोध्या में राममंदिर बन जाएगा। यूपी के मतदाताओं को रिझाने के लिए एक घोषणा रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने की है यूपी में बुलेट ट्रेन चलाने की। पहली बुलेट ट्रेन चली नहीं, दूसरी की घोषणा हो गई। मोदी और उनके सहयोगियों का मानना है कि जनता बेवकूफ है और ऐसी घोषणाएं उसे रिझा सकती हैं, पर इसका हश्र सामने आ जाएगा।

सवाल है, यूपी में चुनाव के समीकरण क्या हैं ? जहां तक कांग्रेस का सवाल है, लाख कोशिशों के बावजूद उसका फिर से उठकर खड़ा हो पाना मुश्किल लगता है। पहले मोदी के लिए, बाद में नीतीश के लिए और अब यूपी में कांग्रेस के लिए काम कर रहा इलेक्शन कैम्पेनर और योजनाकार प्रशांत किशोर दावा कर रहा है कि यूपी में अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी। यह हास्यास्पद है। अगर ऐसे प्रोफेशनल योजनाकारों के दम पर ही चुनाव जीते जा सकते तो फिर जनता के मतों की जरूरत क्या होती ? प्रशांत किशोर जैसे चुनाव योजनाकारों का आना ही इस जनतंत्र की सच्चाई को सामने रख देता है। ज्यादातर गंभीर राजनीतिक विश्लेषकों ने यह मत व्यक्त किया है कि यूपी में कांग्रेस की स्थिति में सुधार संभव नहीं है। वह सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आ सकती। यूपी में हार के साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का खात्मा संभव है। यह अलग बात है कि लालू-नीतीश और वामपंथी उसके साथ हैं, पर वामपंथियों को पश्चिम बंगाल में अपना हश्र नहीं भूलना चाहिए। वैसे भी यूपी में वामपंथियों की कोई ताकत नहीं है। जहां तक मुलायम सिंह का सवाल है, इस बार चुनाव में समाजवादी पार्टी का सूपड़ा जरूर साफ हो सकता है, क्योंकि अखिलेश-मुलायम के शासन से जनता बुरी तरह त्रस्त हो गई है। मुलायम को अपनी हार साफ दिखाई पड़ रही है और वे हताशा में कुछ ऐसे कदम उठा रहे हैं, जिनका अखिलेश ने भी विरोध किया। मुलायम के भाई शिवपाल यादव ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल का विलय सपा में करा दिया। पर अखिलेश के विरोध के कारण यह विलय रद्द करना पड़ा। कहा जा रहा है कि चुनाव में क्या रणनीति अपनाई जाए, इसे लेकर मुलायम के कुनबे में फूट पड़ चुकी है। सपा वैसे भी एक परिवार और कुनबे की पार्टी बन कर रह गई है। इसके कई नेताओं में भारी असंतोष है और उनमें से कुछ मौका मिलते ही भाजपा या बसपा में जा सकते हैं। कुल मिला कर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सपा का भी खात्मा हो सकता है। मुलायम और उनके कुनबे ने लंबे समय तक केंद्र और यूपी में सत्ता का मजा लिया है, पर यादव मतों के आधार पर और गैंगस्टरों के सहयोग से उनका दोबारा सत्ता में आ पाना असंभव प्रतीत होता है।

ऐसे में, राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मायावती फिर से यूपी की सत्ता पर काबिज हो सकती हैं। मायावती ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी है। जोड़-तोड़ और किसी भी तिकड़म में मायावती भाजपा और सपा नेताओं से पीछे नहीं हैं। धनबल भी उनके पास कम नहीं। दलितों, पिछड़ों के साथ उच्च जातियों के वोटरों को भी साधने की कला का प्रदर्शन उन्होंने सफलतापूर्वक किया था। ऐसा वे फिर कर सकती हैं। उनकी जीत इसलिए भी संभव है, क्योंकि जनता में हताशा है। यूपी में मायावती के राज को गुंडाराज कहा गया था और अखिलेश-मुलायम के राज को महागुंडाराज। यह ठीक ही कहा गया था। अखिलेश ने पांच साल तक यूपी में राज कर लिया। इस दौरान यूपी लगातार गर्त में जाता रहा। अखिलेश सरकार माफिया और गुंडों के भरोसे चलती रही। मुलायम जो एक समय मुसलमानों के मसीहा माने जाते थे और मौलाना मुलायम के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे, कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यकों का भी उन पर भरोसा नहीं रहा। इसके पीछे मुजफ्फरनगर और अन्य दंगों में सपा की संदिग्ध भूमिका भी रही है। अल्पसंख्यक मायावती के करीब आ रहे हैं। मायावती की नीति है कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के साथ ऊंची जाति के वोटरों को भी अपने पक्ष में गोलबंद कर लिया जाए। इसके लिए वे साम-दाम- दंड-भेद, कोई भी नीति अपनाने से गुरेज नहीं करेंगी। अगर उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, फिर भी इतनी सीटें तो मिल जाएंगी कि जोड़-तोड़ कर या गठबंधन कर सरकार बना लें। बहरहाल, यूपी की जनता को गुंडाराज, महागुंडाराज और भाजपा के राक्षसराज में से ही किसी एक को चुनना है। अन्य विकल्प मतदाताओं के सामने नहीं है।

कैराना से 'पलायन' समाज को बांटकर वोट कमाने की कवायद

- राम पुनियानी

सन 2014 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले, उत्तरप्रदेश के मुजफ्फरनगर में भड़के सांप्रदायिक हिंसा के दावानल में 80 मुसलमान मारे गए थे और हजारों को अपने घर-गांव छोड़कर भागना पड़ा था। ऐसा लगता है कि उत्तरप्रदेश में सन 2017 में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर, भाजपा ने अपनी दंगा भड़काऊ मशीनरी को पुन: सक्रिय कर दिया है।

कैराना लोकसभा चुनाव क्षेत्र से निर्वाचित भाजपा सांसद हुकुम सिंह ने हाल में यह दावा किया कि उत्तरप्रदेश के मुस्लिम-बहुल कैराना शहर से सैंकड़ों हिंदू परिवारों को मजबूरी में पलायन करना पड़ा है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने इलाहाबाद में 12-13 जून, 2016 को आयोजित पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस मुद्दे को उठाकर राष्ट्रीय स्तर पर सनसनी फैलाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी बैठक में भाषण दिया परंतु जैसी कि परंपरा सी बन गई है, उन्होंने केवल विकास की बात की और सांप्रदायिकता की आग भड़काने का काम शाह पर छोड़ दिया। प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार पर हमला बोलते हुए शाह ने आह्वान किया कि राज्य की जनता को ऐसी पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए जो कैराना से ''पलायन'' रोकने में असफल रही है।

बैठक में भाजपा नेताओं ने कश्मीरी पंडितों के ''पलायन'' की ओर इशारा करते हुए कहा कि कैराना, दूसरा कश्मीर बनने की राह पर है। हुकुम सिंह ने ऐसे 346 हिंदू परिवारों की सूची जारी की, जो उनके अनुसार कैराना छोड़ कर चले गए थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से भी इसकी शिकायत की गई और आयोग ने तुरंत राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दिया।

सच यह है कि मुंबई और अहमदाबाद जैसे शहरों में सुनियोजित ढंग से मुसलमानों को उनकी बस्तियों में कैद कर दिया गया है। सन 1992-93 की मुंबई हिंसा के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आई। मुम्बरा, भिंडी बाजार व जोगेश्वरी ऐसे इलाकों में शामिल हैं, जहां मुसलमानों की आबादी केंद्रित हो गई है। शहर के बाकी इलाकों में बिल्डरों ने मुसलमानों को मकान बेचना और किराए पर देना बंद कर दिया है। अहमदाबाद में हालात इससे भी खराब हैं। वहां जुहापुरा जैसी कई ऐसी बस्तियां बस गई हैं जहां केवल मुसलमान रहते हैं। इन बस्तियों को सांप्रदायिक तत्व 'मिनी पाकिस्तान' बताते हैं और वहां नागरिक सुविधाओं का नितांत अभाव है।

बैठक के अगले दिन, हुकुम सिंह अपनी बात से कुछ पीछे हटते दिखे। उन्होंने कहा कि ''मेरी टीम के किसी सदस्य ने गलती से हिंदू परिवार शब्द का उपयोग कर दिया। मैंने उसे बदलने को कहा था। मैं अपनी इस बात पर कायम हूं कि यह हिंदू-मुस्लिम मसला नहीं है। यह केवल उन लोगों की सूची है, जिन्हें मजबूरी में कैराना छोड़ कर जाना पड़ा है।''

दो बड़े राष्ट्रीय अखबारों ने सूची की पड़ताल की। उत्तरप्रदेश सरकार ने भी मामले की जांच के आदेश दिए। समाचारपत्रों की पड़ताल से यह जाहिर हुआ कि ''सूची में ऐसे लोगों के नाम हैं जो मर चुके हैं, जो दस साल या उससे भी पहले कैराना छोड़कर चले गए थे और ऐसे लोगों के भी, जिन्होंने बताया कि वे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल या अच्छी नौकरी की तलाश में दूसरे शहरों में जा बसे हैं'' (द इंडियन एक्सप्रेस, 14 जून, 2016)। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि मुस्लिम गुंडों के गिरोह हिंदुओं को आतंकित कर रहे हैं। इनमें से एक नाम मुकीम काला नामक अपराधी के गिरोह का बताया जा रहा है। दिलचस्प यह है कि जब काला को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था, तब उस पर 14 व्यक्तियों की हत्या के आरोप थे। इनमें से 11 मुसलमान और 3 हिंदू थे। स्थानीय प्रशासन ने जब सूची की जांच की तो उसने पाया कि 119 व्यक्तियों में से 66 पांच साल पहले ही अपने घर छोड़ गए थे (हिंदुस्तान टाईम्स, 14 जून, 2016)।

भाजपा क्या करना चाह रही है, यह समझना मुश्किल नहीं है। वह उत्तरप्रदेश के एक मुस्लिम-बहुल इलाके से हिंदुओं के कथित पलायन को मुद्दा बनाकर भावनाएं भड़काना चाहती है। आग में घी डालने के लिए उसने इसकी तुलना कश्मीर घाटी से पंडितों के पलायन से करनी शुरू कर दी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ताधारी दल के ज़िम्मेदार नेता एक ऐसे व्यक्ति के दावे के समर्थन में सार्वजनिक वक्तव्य जारी कर रहे हैं, जो स्वयं अपनी बात से पीछे हट रहा है।

सच यह है कि मुंबई और अहमदाबाद जैसे शहरों में सुनियोजित ढंग से मुसलमानों को उनकी बस्तियों में कैद कर दिया गया है। सन 1992-93 की मुंबई हिंसा के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आई। मुम्बरा, भिंडीबाजार व जोगेश्वरी ऐसे इलाकों में शामिल हैं, जहां मुसलमानों की आबादी केंद्रित हो गई है। शहर के बाकी इलाकों में बिल्डरों ने मुसलमानों को मकान बेचना और किराए पर देना बंद कर दिया है। अहमदाबाद में हालात इससे भी खराब हैं। वहां जुहापुरा जैसी कई ऐसी बस्तियां बस गई हैं जहां केवल मुसलमान रहते हैं। इन बस्तियों को सांप्रदायिक तत्व 'मिनी पाकिस्तान' बताते हैं और वहां नागरिक सुविधाओं का नितांत अभाव है।

कैराना के पड़ोस में स्थित मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक हिंसा के बाद मुसलमानों का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ था। वहां लवजिहाद के मुद्दे का इस्तेमाल सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए किया गया था। एक भाजपा विधायक ने सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियो क्लिप अपलोड की, जिसमें मुसलमानों की एक भीड़ को दो युवकों की पीट-पीटकर हत्या करते हुए दिखाया गया था। बाद में यह सामने आया कि यह क्लिप पाकिस्तान की थी। इसके बाद कई महापंचायतें आयोजित की गईं, जिनमें ''बहू-बेटी बचाओ'' अभियान शुरू करने की बात कही गई।

मुजफ्फरनगर में हुई भयावह हिंसा में बड़ी संख्या में मुसलमानों के घर नष्ट कर दिए गए। कई गांवों को मुस्लिम-मुक्त क्षेत्र बना दिया गया।

उत्तरप्रदेश में गौमांस के मुद्दे पर भी हिंसा भड़काई गई और मोहम्मद अखलाक नाम के आदमी की खून की प्यासी भीड़ ने पीट-पीटकर जान ले ली। घटना के आठ महीने बाद, अब एक दूसरी लेबोरेटरी में की गई जांच के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि अखलाक के घर से जो मांस मिला था, वह गाय का था। इस मुद्दे पर महापंचायतों को फिर से सक्रिय करने की कोशिश की जा रही है।

कुछ टीवी चैनल और समाचारपत्र, कैराना के मुद्दे पर आधारहीन दुष्प्रचार कर रहे हैं। इससे सांप्रदायिकता का लहर और फैल रहा है। येल विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन से यह सामने आया था कि जिन भी इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा होती है, वहां भाजपा को चुनावों में फायदा होता है। कैराना से कथित पलायन की बात भी वोट की राजनीति का हिस्सा है। यह देखना बाकी है कि मीडिया द्वारा हुकुम सिंह के दावे के झूठ को बेनकाब किए जाने के बाद, भाजपा इस मुद्दे पर कायम रहती है या उससे पीछे हटती है।

(मूल अंग्रेजी से हिन्दी रूपांतरण अमरीश हरदेनिया)

(लेखक आई.आई.टी. मुंबई में पढ़ाते थे और सन् 2007 के नेशनल कम्यूनल हार्मोनी एवार्ड से सम्मानित हैं।)